



## नई शिक्षा नीति—रोजगार के अवसरों में वृद्धि के संदर्भ में योगदान

सरोज रजक

पीएच.डी.शोधार्थी(अर्थशास्त्र)

डॉ. अंजनी कुमार पाण्डेय

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश।

### Article Info

### Publication Issue :

November-December-2023

Volume 6, Issue 6

Page Number : 141-144

### Article History

Received : 02 Dec 2023

Published : 21 Dec 2023

**सारांश:**—शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज में चलने वाली वह निरन्तर प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य इंसान की आन्तरिक शक्तियों का विकास करना और उसके व्यवहार में सुधार लाना है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। गौरतलब है कि आजादी के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति सन् 1986 में बनाई गई थी जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी। इसमें 1992 में कुछ संशोधन भी किये गये किन्तु इसका ढांचा मूलतः अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर ही केन्द्रित रहा।

**मूलशब्द** :— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल युग, शिक्षार्थियों, ज्ञान, शिक्षा।

**प्रस्तावना** :— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020(एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति 2020 भारत को बदलने में सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है। इसका उद्देश्य धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना, सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवन, ज्ञान, समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को, छात्रों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिए और संवैधानिक मूल्यों, अपने देश और एक बदलती दुनिया के साथ एक संबंध पैदा करना चाहिए। इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास करना है, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन का समर्थन करते हैं और वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबंधित होता है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवृत्ति के हों। यह एक व्यक्ति को रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत, तकनीकी, व्यावसायिक विषयों सहित क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करने और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा भावना और 21 वीं सदी के कौशल को आवश्यक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाती है। नई शिक्षा नीति वर्तमान प्रणाली में कुछ मौलिक परिवर्तन लाती है, और इसमें मुख्य आकर्षण बहु-विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जिसमें प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक छात्र पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, बेहतर छात्र अनुभव के लिए मूल्यांकन और समर्थन, एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विश्वविद्यालय और कॉलेजों में उत्कृष्ट सहकर्मियों-समीक्षा कार्य और प्रभावी ढंग से बीज अध्ययन का समर्थन करेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 पांच स्तंभों पर केंद्रित है वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबदेही-निरंतर सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए। इसे समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के रूप में नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 में सूचीबद्ध पूर्ण और उत्पादक रोजगार और अच्छे काम की अग्रसर होना, नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है और 2040 तक भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों को बदलने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए तैयार करती हैं जिससे वो नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रकार नई शिक्षा नीति बहु-विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित, संचार, समस्या-समाधान, तार्किक तर्क और व्यावसायिक प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।

**अध्ययन का उद्देश्य:**— इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है तथा नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का विश्लेषण करना है। इसके अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. नई शिक्षा नीति 2020 को पेश करना।
2. नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं को देखना।
3. उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को दर्शाने लिए।
4. शिक्षा पर राज्य के खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 4 से बढ़ाकर 6 करने की एक झलक देने के लिए।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई अपडेट** :— स्कूली शिक्षा को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्री प्राइमरी से जुड़ी एक नई अपडेट दी है।

शिक्षा मंत्रालय ने प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा को नीति में जोड़ने की एक नई पलह की है। अब कोरोनावायरस संक्रमण के चलते हुए शिक्षा नीति द्वारा प्री-प्राइमरी को भी ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ा जाएगा।

स्कूलों में राज्य के साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के केन्द्र शिक्षा मंत्रालय ने। मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में समग्र शिक्षा के नियमों में बदलाव को चर्चा की। इन बदलाव पर अभी कोई सहमति नहीं दी गई है लेकिन मंत्रालय ने इसे जल्द ही सीबीएसई, एन.सी.ई.आर.टी. और साथ-साथ राज्य के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। अब ब्लॉक स्तर की टीम में ऑनलाइन पढ़ाई पर पूरी तरह से नजर रखेंगे। जिससे उनकी शिक्षा में आई कमी को तुरंत पाया जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा।

**नई शिक्षा नीति के लाभकारी प्रभाव :-** पहले छात्रों के पास अध्ययन के लिए केवल एक ही विषय चुनने का विकल्प था, लेकिन अब अलग-अलग विषय चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए गणित के साथ-साथ कला और शिल्प का भी विकल्प चुन सकते हैं।

नई शिक्षा नीति किसी भी विषय सीखने के व्यावहारिक पहलू पर केन्द्रित है। क्योंकि यह अवधारण को समझने के लिए बेहतर तरीका माना जाता है।

1. 2000 तक सभी संसिीन और उच्च शिक्षण संस्थान बहु-विषयक बन जाएंगे।
2. हर विषय पर समान रूप से व्यवहार करने पर जोर ।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच नवीन विचारों के समावेश के सहभागिता, महत्त्वपूर्ण सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करना है।

स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों को अनुभव से लाभान्वित करने और इस बीच कहीं काम करने से कौशल प्राप्त करने और फिर बाद में जारी रखने का अवसर प्रदान करेंगे।

**नुकसान :-**भाषा का कार्यान्वयन यानी क्षेत्रीय भाषाओं में जारी रखने के लिए 5 वीं कक्षा तक बढ़ाना एक बड़ी समस्या हो सकती है। बच्चे को क्षेत्रीय भाषा के प्रति कम दृष्टिकोण होगा, जो 5वीं कक्षा पूरा करने बाद आवश्यक है। बच्चों को संरचनात्मक तरीके से सीखने के अधीन किया गया है। जिससे उनके छोटे दिमाग पर बोझ बढ़ सकता है।

**निष्कर्ष :-**केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, यदि उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। 34 वर्ष पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है।

**संदर्भ :-**

1. प्रकाश कुमार, 21 वीं सदी की माँग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. प्रो.के.एल.शर्मा, दैनिक भास्कर, म.प्र. संस्करण पृष्ठ संख्या-2, 24 अगस्त 2020
4. गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21 वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति पृष्ठ संख्या 4, 22 अगस्त 2020
5. सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020 पृष्ठ संख्या 80-81